



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 155]
No. 155]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 1987/चैत्र 9, 1909
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 1987/CHAITRA 9, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 340 (अ):— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित
आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. का. 132”

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश 1987

संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात
निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण)
सं. 3 आदेश, 1987 है।

2. इस आदेश के निर्वाचन के लिए साधारण खंड अधिनियम, 1897
(1897 का 10) वैसे ही लागू होगा जैसे वह किसी केन्द्रीय अधिनियम
के निर्वाचन के लिए लागू होता है।

3(1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल,
1986 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में :—

(क) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य
के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में 1 अप्रैल, 1985
को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में उन राज्यों में से
प्रत्येक के लिए लिए गए उधारे और दिए गए उधारों
लेखे शुद्ध व्याज के दायित्व मद्दे उक्त सारणी के स्तम्भ
(2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, इस संबंध में वित्त
आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत की संवित निधि
पर भारित होंगी :—

सारणी

राज्य	(रुप लाख में)
1	2
असम	5401.07
हिमाचल प्रदेश	527.24
जम्मू कश्मीर	3796.49

1	2
मणिपुर	486.62
मेघालय	268.40
नागालैंड	673.08
उड़ीसा	4949.56
राजस्थान	2748.87
सिक्किम	131.37
पश्चिमी बंगाल	7667.26

परन्तु यदि उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किए गए वास्तविक लिए गए उधारों और दिए गए उधारों के अंक या लिए गए उधारों पर ब्याज की धरे ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदानों के आवधारण में हिस्सा में लिए गए सुसंगत अकों से भिन्न हैं तो इस प्रकार दिए गए अनुदान की रकम किसी ऐसी राशि या राशियों के विरुद्ध समायोजित की जाएगी जो उस राज्य को उसी प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किन्हीं उत्तरवर्ती वर्षों में संवेद्य हो ;

(ख) नीचे की साहूणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में 1 अप्रैल, 1979, 1980, 1981, 1982 और 1983 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्षों में, उन राज्यों में से प्रत्येक के नए लिए गए उधारों और दिए गए उधारों लेखें शुद्ध ब्याज के बायित्व मध्ये उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियाँ संविधान (राजस्व वितरण) अध्यादेश 1981 संविधान (राजस्व वितरण) अध्यादेश, 1982 संविधान (राजस्व वितरण) अध्यादेश 1983 और संविधान (राजस्व वितरण) अध्यादेश, 1984 के अधीन शुद्ध ब्याज के बायित्व मध्ये दिए गए अनुदान को हिस्सा में लेने के पश्चात् इस संबंध में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत की संवित निधि पर भारित होगी :-

सारणी

राज्य	(रुपए लाख में)
1	2
हिमाचल प्रदेश	362.36
मेघालय	43.41
उड़ीसा	86.59
सिक्किम	370.32

(2) उपर्युक्त (1) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन, किसी राज्य को संवेद्य कोई राशि या राशियाँ, संविधान (राजस्व वितरण) अध्यादेश, 1985 के पैरा 4 के उपपैरा (1) के अनुसरण में उस राज्य को संवेद्य राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

जील सिंह, राष्ट्रपति

[सं. फा. 19(3)87-बि I]

एस. रामय्या, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 30th March, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 340(E):—The following Order made by the president is published for general information:

“C.O. 132”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 3 ORDER, 1987

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 1987.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1986 as grants-in-aid of the revenues of—

(a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards net interest liability on account of fresh borrowings and lendings of each of those States, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1985, as per the recommendations of the Finance Commission in this regard:—

TABLE

State	(Rupees in lakhs)
(1)	(2)
Assam	5401.07
Himachal Pradesh	527.24
Jammu and Kashmir	3796.49
Manipur	486.62
Meghalaya	268.40
Nagaland	673.08
Orissa	4949.5
Rajasthan	2748.87
Sikkim	131.37
West Bengal	7667.26

Provided that if the figures of actual borrowings and lendings as revealed in the accounts of that year, or the rates of interest on borrowings are different from the relevant figures taken into account in determining the grants specified above, the amount of grant so paid shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose;

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards net interest liability on account of fresh borrowings and lendings of each of those States, in the financial years commencing on the 1st day of April, 1979, 1980, 1981, 1982 and 1983 after taking into account the grants paid towards net interest liability under the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1981, the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1982, the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1983 and the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1984, as per the recommendations of the Finance Commission in this regard:—

TABLE

State	(Rupees in lakhs)
(1)	(2)
Himachal Pradesh	362.36
Meghalaya	43.41
Orissa	86.59
Sikkim	370.32

(2) Any sum or sums payable under clauses (a) and (b) of sub-paragraph (1) to any State shall be in addition to the sum or sums payable to that State in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1985

ZAIL SINGH,
President.

[No. F. 19(3)/87-LI]
S. RAMAIAH, Secy.

